

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1263
सोमवार, 11 फरवरी, 2019/22 माघ, 1940 (शक)

रोजगार की वृद्धि दर

1263. श्री धर्मेन्द्र यादव:

डॉ० प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:
श्रीमती रंजनबेन भट्ट:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2014 से कितने वास्तविक रोजगार अवसरों का सृजन किया गया है;
- (ख) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए रोजगार के संबंध में वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने वर्ष 2014 के पश्चात् रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे हैं;
- (घ) क्या रोजगार की वार्षिक वृद्धि अर्थव्यवस्था की वृद्धि के समरूप नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या अनुक्रिया है;
- (ङ) क्या रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए श्रम गहन विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में चिन्हित श्रम गहन विनिर्माण उद्योगों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (च): श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर आयोजित किए गए उपलब्ध श्रम बल सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य प्रमुख एवं सहायक स्थिति (यूपीएसएस) दृष्टिकोण पर आधारित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का अनुमान 2012-13 में 51.0%, 2013-14 में 53.7% एवं 2015-16 में 50.5% था। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अनुमान के अनुसार, देश में स्थाई कीमतों (आधार वर्ष 2011-12) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की संगत वृद्धि दर 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 के दौरान क्रमशः 5.5%, 6.4% एवं 8.2% थी।

इसके अतिरिक्त, श्रम ब्यूरो के अप्रैल, 2016 में प्रारंभ किए गए पुनर्संजित तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) में गैर-फार्म औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बड़े भाग में उत्तरवर्ती तिमाहियों में रोजगार की स्थिति में तुलनात्मक परिवर्तन पाया गया। इस सर्वेक्षण में 8 प्रमुख क्षेत्रों, नामतः विनिर्माण, निर्माण, व्यवसाय, परिवहन, आवास एवं रेस्तरा, आईटी/बीपीओ, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को शामिल किया गया। रोजगार में क्षेत्र-वार परिवर्तन के ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2017 में सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) प्रारंभ किया, जो शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही अनुमानों के साथ-साथ रोजगार एवं बेरोजगारी पर श्रम बल संबंधी वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया एक नियमित एवं निरंतर सर्वेक्षण है। वर्ष 2017-2018 (जुलाई, 2017 से जून, 2018) हेतु, एनएसएसओ ने सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया है तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) को मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसने इसको अनुमोदन दे दिया है। एनएसएसओ वर्तमान में जुलाई, 2017 से दिसम्बर, 2018 की अवधि के तिमाही आंकड़े संशोधित कर रहा है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), तथा पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार का ब्यौरा अनुबंध-11 में दिया गया है।

सरकार ने श्रम-बहुल विनिर्माण को कार्यनीतिक रूप से बढ़ावा देने एवं पर्यटन तथा कृषि-आधारित उद्योगों के संवर्धन द्वारा रोजगार अवसरों का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 25 जनवरी, 2019 तक इस योजना के तहत कुल 15.59 करोड़ ऋणों को संस्वीकृत किया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 में नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु उनके पंजीकरण की तारीख से ईपीएस एवं ईपीएफ के नियोक्ताओं के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान 01.04.2018 से अगले 3 वर्षों के लिए कर रही है। 4 फरवरी, 2019 तक 1.06 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले 1.31 लाख प्रतिष्ठानों को लाभांशित किया गया है।

अनुबंध-1

रोजगार की वृद्धि दर के संबंध में लोक सभा के दिनांक 11.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1263 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित त्वरित तिमाही रोजगार सर्वेक्षणों के अनुसार आठ क्षेत्रों में रोजगार में क्षेत्र-वार परिवर्तन

(लाख में)

क्र.सं.	क्षेत्र	1 अप्रै. 16 की तुलना में 1 जुला., 16	1 जुला. 16 की तुलना में 1 अक्तू., 16	1 अक्तू. 16 की तुलना में 1 जन. 17	1 जन., 17 की तुलना में 1 अप्रै., 17	1 अप्रै., 17 की तुलना में 1 जुला., 17	1 जुलाई, 17 की तुलना में 1 अक्तूबर, 17
1	विनिर्माण	-0.12	0.24	0.83	1.02	-0.87	0.89
2	निर्माण	-0.23	-0.01	-0.01	0.02	0.10	-0.22
3	व्यापार	0.26	-0.07	0.07	0.29	0.07	0.14
4	परिवहन	0.17	0.00	0.01	0.03	-0.03	0.20
5	आवास और रेस्तरां	0.01	-0.08	0.00	0.03	0.05	0.02
6	आईटी/बी पीओ	-0.16	0.26	0.12	0.13	0.02	0.01
7	शिक्षा	0.51	-0.02	0.18	0.02	0.99	0.21
8	स्वास्थ्य	0.33	0.00	0.02	0.31	0.31	0.11
	कुल	0.77	0.32	1.22	1.85	0.64	1.36

*स्रोत: श्रम ब्यूरो

अनुबंध-11

रोजगार की वृद्धि दर के संबंध में लोक सभा के दिनांक 11.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1263 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन

सृजित रोजगार					
योजनाएं/वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	357502	323362	407840	387184	311976 (31.12.2018 तक)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (मानव-दिवस लाख में)	16619	23514.19	23564.07	23412.35	20940.23 (30.01.2019 तक)
प्रशिक्षण के उपरांत (डीडीयू-जीकेवाई) रोजगार में नियोजित अभ्यर्थी (व्यक्तियों की संख्या)	54196	109512	147883	75787	119331 (जन., 2019 तक)
कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों का नियोजन डीएवाई-एनयूएलएम (व्यक्तियों की संख्या)	63115	33664	151901	115416	107750 (23.01.2019 तक)